>

Title: Need to include dew as natural calamities and give compensations to affected farmers .

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जनवरी 2011 में मध्य प्रदेश में भंयकर पाले के कारण लगभग 36 लाख हेक्टेअर भूमि पर बोई हुयी दलहन और तिलहन की फसल को नुकसान हुआ था। लगभग 33 लाख किसान इसमें प्रभावित हुए थे। इसका जो आकलन हुआ था, जिसमें 7,624 करोड़ रूपए की फसल नष्ट हुयी थी। ऐसा अनुमान है कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों को 1,400 करोड़ रूपए के लगभग राहत पहुंचाने का काम किया है। उसी बीच में हम लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि पाले को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए तब माननीय वित्त मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह गठित हुआ था और उसकी बैठक भी 26 मई, 2011 को हुयी थी। एक केन्द्रीय अध्ययन दल वहां गया था। अध्ययन दल ने अपनी सिफारिश भी की है कि वहां के किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय आपदा में पाले को भी शामिल किया जाए। यह विषय सरकार के पास विचाराधीन है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि किसानों को कम से कम 2442 करोड़ रूपये जो किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हेतु उनको राहत दी जाए। राज्य सरकार ने तो अपने पैसे से सहयता की लेकिन भारत सरकार का भी यह कर्तव्य बनता है कि प्रभावित किसानों को अपनी तरफ से सहायता पहुंचाने का काम करे। मेरी मांग है कि मंत्री समूह तत्काल निर्णय ले और पाले को प्राकृतिक आपदा में शामिल करते हुए मध्य प्रदेश के किसानों को 2442 करोड़ रूपये राहत की राशि देने का काम करे।